



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 162]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 20, 2018/चैत्र 30, 1940

No. 162]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 20, 2018/CHAITRA 30, 1940

देना बैंक

अधिसूचना

मुम्बई, 6 मार्च, 2018

**पत्र सं. मुख्य/मु.स.प्र./अधौ/नोट-79/2018.**—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 के साथ धारा 12 की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, देना बैंक निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, देना बैंक (अधिकारी) सेवा विनियमन, 1979 में आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बना रहा है, अर्थात्:—

1. (1) इन विनियमों को देना बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियमन, 2017 कहा जाएगा।  
(2) इन विनियमों में अन्यथा किए गए प्रावधानों को छोड़कर, ये विनियम 1 नवंबर, 2007 से लागू माने जाएंगे।
2. देना बैंक (अधिकारी) सेवा विनियमन, 1979 (इसके बाद विनियमन कहा जाएगा) में, विनियम 3 में:-

- (i) खण्ड (एफ) के लिए, उसके स्थान पर निम्नानुसार लिखा जाए, अर्थात्:-

‘(एफ) “परिवार” से तात्पर्य है अधिकारी की पत्नी/पति, पूर्णतः निर्भर अविवाहित पुत्र/पुत्री (सौतेले और गोद लिए गए शामिल), चालीस प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले शारीरिक रूप से विकलांग भाई या बहन और माता-पिता जो सामान्यतः अधिकारी के साथ निवास करते हों और अधिकारी पर पूर्णतः निर्भर हों।’

स्पष्टीकरण – इस खण्ड के प्रयोजन हेतु, कोई पुत्र/पुत्री या माता-पिता या शारीरिक रूप से विकलांग भाई या बहन अधिकारी पर पूर्णतः निर्भर माने जाएंगे यदि ऐसे पुत्र/पुत्री, माता-पिता, भाई या बहन की मासिक आय रु. 3,500/- प्रति माह से अधिक न हो।

यदि माता-पिता में से किसी एक की आय रु.3,500/- प्रतिमाह से अधिक हो या दोनों की कुल मासिक आय रु.3,500/- प्रति माह से अधिक हो, तो दोनों को अधिकारी पर पूर्णतः निर्भर नहीं माना जाएगा।’

(ii) खण्ड (ओ) को हटा दिया जाएगा।

3. कथित विनियम के विनियम 4 में :-

(i) उप-विनियम (4ए) हटा दिया जाएगा;

(ii) उपर्युक्तानुसार उप-विनियम (4ए) को हटाने के पश्चात, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा; यथा :-

“(5) 1 नवंबर 2007 से प्रभावी होते हुए; प्रत्येक ग्रेड के लिए निर्धारित वेतनमान निम्नानुसार होगा:-

(ए) उच्च कार्यपालक ग्रेड

वेतनमान VII = रु.46800 – 1300/4 – 52000

वेतनमान VI = रु.42000 – 1200/4 – 46800

(बी) वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड

वेतनमान V = रु.36200 – 1000/2 – 38200 – 1100/2 – 40400

वेतनमान IV = रु.30600 – 900/4 – 34200 – 1000/2 – 36200

(सी) मध्यम प्रबंधन ग्रेड

वेतनमान III = रु.25700 – 800/5 – 29700 – 900/2 – 31500

वेतनमान II = रु.19400 – 700/1 – 20100 – 800/10 – 28100

(डी) कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड

वेतनमान I = रु.14500 – 600/7 – 18700 – 700/2 – 20100 – 800/7 – 25700

**स्पष्टीकरण** — प्रत्येक अधिकारी जो 31 अक्तूबर, 2007 को लागू वेतनमान द्वारा शासित हैं उन्हें 1 नवंबर, 2007 को इस उप-विनियम में दिए गए वेतनमान में स्टेज-से-स्टेज आधार पर फिट किया जाएगा, अर्थात् पहली स्टेज से संबंधित वेतनमान में समनुरूप वेतनमान में फिट किया जाएगा और हमेशा की तरह वर्षगांठ तारीख पर वेतनवृद्धि देय होगी जबतक कि अन्यथा प्रावधान न किया गया हो।

(6) उप-विनियम (1), (2), (3), (4) और (5) में किसी भी बात का यह आशय नहीं होगा कि बैंक में हर समय, इन सभी ग्रेड में अधिकारी सेवारत होना अपेक्षित है।”

4. कथित विनियमों के विनियम 5 में, -

(ए) उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम, के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम होगा, अर्थात्:-

“(1) विनियम 4 के उप- विनियम (5) के प्रावधानों के अध्यधीन, 1 नवंबर, 2007 को और से, निम्नलिखित के अध्यधीन वेतनवृद्धियां प्रदान की जाएंगी, अर्थात्:-

(ए) विनियम 4 के उप- विनियम (5) में उल्लिखित वेतनमानों में निर्धारित वेतनवृद्धियां, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी की शर्त के अध्यधीन, वार्षिक आधार पर मिलेंगी और जिस महीने में वेतनवृद्धि देय होगी उस माह की पहली तारीख को प्रदान की जाएंगी;

(बी) कनिष्ठ प्रबंधन वेतनमान-I में अधिकारी, जो उच्चतर वेतनमान के शीर्ष पर पहुँचने के बाद मध्यम प्रबंधन ग्रेड स्केल-II के वेतनमान में आ गए हैं, वे प्रत्येक तीन-वर्ष-सेवापूर्ति हेतु चार स्टैगेशन वेतनवृद्धि हेतु पात्र होंगे; इनमें से पहली दो वेतनवृद्धि प्रत्येक रु. 800/- की और अगली दो प्रत्येक रु. 900/- की होंगी:

बशर्ते जिन अधिकारियों ने यथा 1 नवंबर, 2007 को दूसरी स्टैगेशन वेतनवृद्धि प्राप्त करने के बाद तीन या अधिक वर्ष पूरे कर लिए हों उन्हें 1 नवंबर, 2007 को तीसरी स्टैगेशन वेतनवृद्धि मिलगी

और दूसरी स्टैग्रेशन वेतनवृद्धि प्राप्त करने के बाद उनके द्वारा छः वर्ष पूरी करने पर 1 नवंबर, 2008 को या उसके बाद एक और स्टैग्रेशन वेतनवृद्धि मिलेगी;

- (सी) मध्य प्रबंधन वेतनमान स्केल-II में अधिकारी, जो उच्चतर वेतनमान के शीर्ष पर पहुँचने के बाद मध्यम प्रबंधन ग्रेड स्केल-III के वेतनमान में आ गए हैं, वे प्रत्येक तीन वर्ष सेवापूर्ति हेतु प्रत्येक रु.900/- के तीन स्टैग्रेशन वेतनवृद्धि हेतु पात्र होंगे:

वशर्ते जिन अधिकारियों ने यथा 1 नवंबर, 2007 को पहली स्टैग्रेशन वेतनवृद्धि प्राप्त करने के बाद तीन या अधिक वर्ष पूरे कर लिए हों उन्हें 1 नवंबर, 2007 को पहली स्टैग्रेशन वेतनवृद्धि मिलेगी और पहली स्टैग्रेशन वेतनवृद्धि प्राप्त करने के बाद उनके द्वारा छः वर्ष पूरी करने पर 1 नवंबर, 2008 को या उसके बाद एक और स्टैग्रेशन वेतनवृद्धि मिलेगी:

वशर्ते कि मध्यम प्रबंधन ग्रेड स्केल-III में नियुक्त या पदोन्नत किए गए अधिकारी प्रत्येक तीन वर्ष-सेवापूर्ति हेतु प्रत्येक रु.900/- के चार स्टैग्रेशन वेतनवृद्धि हेतु पात्र होंगे या;

वशर्ते जिन अधिकारियों ने पहले ही दो स्टैग्रेशन वेतन वृद्धि प्राप्त कर ली हो और यथा 1 नवंबर, 2007 को दूसरी स्टैग्रेशन वेतनवृद्धि प्राप्त करने के बाद पूरे कर लिए हों उन्हें 1 नवंबर, 2007 को तीसरी स्टैग्रेशन वेतनवृद्धि मिलेगी और दूसरी स्टैग्रेशन वेतनवृद्धि प्राप्त करने के बाद उनके द्वारा छः वर्ष पूरी करने पर 1 नवंबर, 2008 को या उसके बाद चौथी स्टैग्रेशन वेतनवृद्धि मिलेगी।

वशर्ते कि अगले उच्च स्तर / ठहराव वेतन वृद्धि / वेतनवृद्धियों में ऐसे वेतन वृद्धि की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब किसी प्रस्ताव में पदोन्नति से इनकार कर दिया जाए।

**स्पष्टीकरण—** इस उप-विनियम के तहत अगले वेतनमान में ऐसी वेतनवृद्धियों को प्रदान किए जाने से पदोन्नति नहीं हो जाएगी और उन्हें प्राप्त विशेष सुविधाएं, अनुलाभ तथा उनके कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां उनके वास्तविक पद के अनुरूप जारी रहेंगी।

- (बी) उप-विनियम (2) में, -

- (i) स्पष्टीकरण में, खण्ड (ई) के बाद और नोट से पहले निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

“(एफ) 1 नवंबर, 2007 को और से, अन्य चीज़े बराबर होने पर, व्यावसायिक अर्हता वेतन (पीक्यूपी) की प्रमात्रा निम्नानुसार संशोधित होगी:-

#### तालिका

जिन्होंने जूनियर एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ़ बैंकर्स या सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ़ बैंकर्स पास कर लिया है।	(i) वेतनमान के शीर्ष पर पहुँचने के एक वर्ष बाद रु.410/- प्रति माह।
जिन्होंने सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ़ बैंकर्स के दोनों भाग पास किया है।	(i) वेतनमान के शीर्ष पर पहुँचने के एक वर्ष बाद रु.410/- प्रति माह। (ii) वेतनमान के शीर्ष पर पहुँचने के दो वर्ष बाद रु.1030/- प्रति माह;

वशर्ते कि यदि कोई अधिकारी वेतनमान के शीर्ष पर पहुँचने के पश्चात् जूनियर एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ़ बैंकर्स या सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ़ बैंकर्स (इनमें से कोई एक या दोनों भाग) की अर्हता प्राप्त करता है, तो ऐसी अर्हता प्राप्त करने की तारीख से, उसे व्यावसायिक अर्हता वेतन (पीक्यूपी) की पहली किस्त प्रदान की जाएगी और पीक्यूपी की बाद की किस्तें, पीक्यूपी की पहली किस्त जारी करने की तारीख के संदर्भ में, जारी की जाएंगी;

बशर्ते कि यदि कोई अधिकारी, पहले ही उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई एक प्राप्त कर चुका है और ऐसी अर्हता प्राप्त करने हेतु उसे कोई वेतनवृद्धि या पीक्यूपी नहीं मिली है, तो उसे 1 नवंबर, 2007 या ऐसी अर्हता प्राप्ति की तारीख, इनमें से जो बाद में हो, से व्यावसायिक अर्हता वेतन (पीक्यूपी) प्रदान किया जा सकता है।”;

(ii) खण्ड (v) हेतु, नोट में, निम्नलिखित खण्डों को बदला जाएगा, यथा:-

“(v) यदि यथा 27 अप्रैल, 2010 कोई अधिकारी, पहले ही खण्ड (iv) में उल्लिखित कथित अर्हताएं प्राप्त कर चुका हो और ऐसी अर्हता प्राप्त करने हेतु उसे कोई वेतन वृद्धि या पीक्यूपी नहीं मिली हो, तो उसे 1 नवंबर 2007 या ऐसी अर्हता प्राप्ति की तारीख, इनमें से जो बाद में हो, से व्यावसायिक अर्हता वेतन (पीक्यूपी) प्रदान की जाएगी।”

(सी) उपनियम (3) में, -

(i) खण्ड (डी) के बाद तथा नोट से पूर्व निम्नलिखित को शामिल किया जायेगा, जो इस प्रकार है :-

“01 नवंबर, 2007 को तथा उक्त तारीख से सभी चीजों के समान रहने पर आवास किराया भत्ता सहित स्थिर व्यक्तिगत वेतन निम्नलिखित दर पर होगा तथा पूरी सेवा अवधि के लिए अवरुद्ध रहेगा :-

#### तालिका

वेतनवृद्धि अंश (रु.)	वेतनवृद्धि अंश पर 01.11.2007 को महंगाई भत्ता (रु.)	जहां बैंक ने आवास सुविधा दी है, वहां कुल स्थिर व्यक्तिगत वेतन (एफपीपी) देय
(क)	(ख)	(ग)
800	58	858
900	65	965
1000	72	1072
1100	79	1179
1200	86	1286
1300	94	1394

(ii) खण्ड (i) तथा (ii) के लिए नोट में निम्नलिखित खण्डों को बदला जायेगा जो इस प्रकार है :-

“(i) स्थिर व्यक्तिगत भत्ता (एफपीए) या स्थिर व्यक्तिगत वेतन (एफपीपी) जैसा कि तालिका के कॉलम सी के अंतर्गत खण्ड (बी), (सी) (डी) या (ई) में दर्शाया गया है, उन अधिकारियों को देय होगा जिन्हें बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है।

(ii) आवास किराया भत्ता के लिए पात्र अधिकारियों के लिए स्थिर व्यक्तिगत भत्ता या स्थिर व्यक्तिगत वेतन तालिका के कॉलम ए तथा बी के खण्ड (ई) के अनुसार प्रतिपादित कुल राशि तथा संबंधित कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया गया आवास किराया भत्ता जब विनियमन 4 के उप-विनियम (2) (3) (4) (5) में उक्त संबंधित वेतनमान की अंतिम वेतनवृद्धि प्राप्त की जानी है, वह होगी।

(iii) नोट के बाद आने वाले खण्ड (ई) को दोबारा से खण्ड (V) की संख्या दी जायेगी तथा निम्नलिखित को इस प्रकार से बदला जायेगा:-

“(v) उपर्युक्त खण्ड (ए) के अनुसार जिस अधिकारी ने अग्रिम वेतनवृद्धि प्राप्त की है, वह वेतनमान के उच्चतम स्तर पर पहुँचने के एक वर्ष बाद उपर्युक्त खण्ड (बी), (सी), (डी) या (ई) में जैसा उल्लिखित है, स्थिर व्यक्तिगत भत्ता /स्थिर व्यक्तिगत वेतन प्राप्त करेंगे”;

5. कथित विनियमों के विनियम 21 में, -

(i) उप-विनियम (3) में नोट हटा दिया जाएगा।

(ii) उप-विनियम (4) में नोट हटा दिया जाएगा।

(iii) उप-विनियम (4) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम तथा नोट जोड़ा जायेगा जो इस प्रकार है:-

“ (5) 01 नवंबर 2007 को तथा उक्त तारीख से, अखिल भारतीय औसत कामगार वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 2836 अंकों में प्रत्येक चार अंक की वृद्धि या कमी पर महंगाई भत्ता देय होगा। (सामान्य) आधार वर्ष 1960=100, वेतन के 0.15% के दर से।

व्याख्या - इस उप-विनियम के उद्देश्य के लिए, -

(ए) महंगाई भत्ता के उद्देश्य के लिए “वेतन” का अर्थ है स्टैगेशन वेतनवृद्धि सहित मूल वेतन,

(बी) जैसा कि विनियम 5 के उप-विनियम (2) की व्याख्या (सी) (डी) (ई) तथा (एफ) में विनिर्दिष्ट व्यावसायिक योग्यता भत्ता (पीक्यूए) या व्यावसायिक योग्यता वेतन (पीक्यूपी) महंगाई भत्ते के योग्य होगी।

6. उक्त विनियमन के विनियम 22 में उप-विनियम (1) तथा (2) के लिए निम्न उप-विनियम को बदला जायेगा जो इस प्रकार है:-

“ (1) 01 नवंबर 2002 को तथा उक्त तारीख से,

(ए) जहां बैंक के द्वारा अधिकारी को आवास सुविधा दी गयी है, अधिकारी जिस वेतनमान में हो उसके प्रथम चरण के मूल वेतन का 1.75 प्रतिशत या आवास का मानक किराया जो भी कम हो, वह राशि उससे वसूली जायेगी।

(बी) जहां बैंक के द्वारा अधिकारी को आवासीय सुविधा नहीं दी गयी है, वहां निम्नलिखित तालिका में विनिर्दिष्ट दर पर वह आवास किराया भत्ते हेतु पात्र होगा, जो इस प्रकार है:

**तालिका**

जहां कार्य स्थल निम्न में है	देय एच.आर.ए होगा
(1)	(2)
(i) मेज़र “ए” श्रेणी के शहर तथा समूह ए में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 8.5%
(ii) क्षेत्र I में अन्य स्थान तथा समूह बी में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 7.5%
(iii) अन्य स्थान	वेतन का 6.5%

परन्तु यदि अधिकारी किराये की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसके द्वारा भुगतान किए गए किराए की वास्तविक राशि में से, वह जिस वेतनमान में हो उसके प्रथम चरण के वेतन का 1.75% घटाकर शेष बची राशि, उसे देय एचआरए होगी। तथापि उसे देय अधिकतम एचआरए, उपर्युक्त कॉलम (2) के अनुरूप एचआरए का 150% होगी।

(2) 01 नवंबर 2007 को तथा उक्त दिन से, -

(ए) जहां बैंक के द्वारा अधिकारी को आवास सुविधा दी गयी है, वहां

वह जिस वेतनमान में है उसके प्रथम चरण के मूल वेतन का 1.20 प्रतिशत या आवास का मानक किराया जो भी कम हो, वह राशि उससे वसूली जायेगी।

(बी) जहां बैंक के द्वारा अधिकारी को आवासीय सुविधा नहीं दी गयी है, वहां निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट दर पर वह आवास किराया भत्ता हेतु पात्र होगा जो इस प्रकार है:-

**तालिका**

जहां कार्य स्थल निम्न में है	देय एच.आर.ए होगा
(1)	(2)
(i) बड़े “ए” श्रेणी के शहर तथा समूह ए में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 8.5%
(ii) क्षेत्र I में अन्य स्थान तथा समूह बी में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 7.5%
(iii) अन्य स्थान	वेतन का 6.5%

परन्तु यदि अधिकारी किराये की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसके द्वारा भुगतान किए गए किराए की वास्तविक राशि में से, वह जिस वेतनमान में हो उसके प्रथम चरण के वेतन का **1.20%** घटाकर शेष बची राशि, उसे देय एचआरए होगी। तथापि उसे देय अधिकतम एचआरए, उपर्युक्त कॉलम (2) के अनुरूप एचआरए का 150% होगी।

**नोट :** अधिकारियों के स्वामित्व के आवास की लागत से संबद्ध मकान किराया भत्ते हेतु उनका दावा, पहले की तरह एचआरए के 150% तक सीमित रहेगा।”;

7. उक्त विनियम के विनियम 23 के अनुसार, –

- उप-विनियम (i) में संख्या, अक्षर तथा शब्द “1 नवंबर 2002,” के स्थान पर संख्या अक्षर तथा शब्द “1 नवंबर 2007” लिखा जाएगा;
- उप-विनियम (2) में संख्या, अक्षर तथा शब्द “1 नवंबर 2002 का प्रथम दिन,” के स्थान पर संख्या अक्षर तथा शब्द “1 नवंबर 2007” लिखा जाएगा;
- उप-विनियम (3), (4), (5) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम बदले जायेंगे जो इस प्रकार हैं:-

“(3) 01 नवम्बर 2007 को तथा उक्त तारीख से यदि कोई अधिकारी समूह ए तथा समूह बी में परियोजना क्षेत्र के रूप में निर्धारित किये जा रहे क्षेत्र में कार्य कर रहा है तो वह समूह ए तथा समूह बी के वर्गीकरण के अनुसार क्रमशः रु.290 या रु.255 की दर से परियोजना क्षेत्र प्रतिपूरक भत्ते का पात्र होगा।

(4) 01 नवंबर 2007 को तथा उस दिन से यदि कोई अधिकारी अकादमिक वर्ष के मध्य में स्थानांतरित होता है तथा पूर्व के स्थान पर उसके एक या अधिक बच्चे विद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं जिस तारीख से वे नये स्थान पर रिपोर्ट करते हैं, उस तारीख से, तो सभी बच्चों के सम्बन्ध में अकादमिक वर्ष की समाप्ति तक रु.700 का मध्य अकादमिक वर्ष स्थानांतरण भत्ता प्राप्त होगा, परन्तु यदि सभी बच्चे पूर्व स्थान पर पढ़ना छोड़ देते हैं तो वैसा भत्ता बंद हो जायेगा।

(5) 01 मई 2010 को या उस तारीख से यदि किसी अधिकारी को बैंक से बाहर सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है तो उसे जिस पद पर प्रतिनियुक्त किया जा रहा है वह उससे संबंधित परिलब्धियां प्राप्त कर सकता है या वह अपने वेतन के अतिरिक्त अपने वेतन का 7.75 प्रतिशत की दर से प्रतिनियुक्त भत्ता जो अधिकतम रु.2300 प्रतिमाह होगा तथा वैसे अन्य भत्ते प्राप्त कर सकता है जो उस स्थान पर बैंक की सेवा में तैनात होने पर उसे प्राप्त होते।

परन्तु यदि वह ऐसी संस्था में प्रतिनियुक्त होता है जो उस जगह स्थित है जहाँ वह प्रतिनियुक्ति के ठीक पूर्व तैनात था तो उसे वेतन का 4 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त होगा परन्तु यह भत्ता अधिकतम प्रति माह रु.1200 होगा।

इसके अतिरिक्त यदि अधिकारी को संकाय सदस्य के रूप में बैंक के प्रशिक्षण संस्थान में प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह वेतन के 4 प्रतिशत की दर से प्रतिनियुक्ति भत्ते हेतु पात्र होगा परन्तु यह भत्ता अधिकतम प्रतिमाह रु.1200 होगा।

(iv) उप-विनियम (8) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम बदले जायेंगे जो इस प्रकार है-

“(8) 01 नवंबर 2007 को तथा उक्त तारीख से यदि दिन में न्यूनतम दो घंटे के अंतराल सहित कार्यालयीन समय बांटा जाता है तो वह अधिकारी प्रतिमाह रु.165 की दर से विभक्त सेवा भत्ते (Split Duty Allowance) हेतु पात्र होगा।”

(v) विनियम (10) में -

(ए) संख्या, अक्षर और शब्द "1 नवंबर 2002" के बदले लिए संख्या, अक्षर और शब्द "1 नवंबर 2007" लिखा जाएगा।

(बी) तालिका के स्थान पर, निम्न तालिका होगी, अर्थात्:

**"तालिका"**

स्थान (1)	दर (2)
i. 1000 मीटर से अधिक किन्तु 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाला स्थान और मर्कारा कस्बा	वेतन का 2% अधिकतम रु.550 प्रतिमाह
ii. 1500 मीटर से अधिक किन्तु 3000 मीटर से कम ऊंचाई वाला स्थान	वेतन का 2 <sup>1/2</sup> % अधिकतम रु.680 प्रतिमाह
iii. 3000 मीटर और अधिक ऊंचाई वाला स्थान	वेतन का 5% अधिकतम रु.1570 प्रतिमाह

8. कथित विनियमों के विनियम 24 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ए) के बदले निम्नलिखित खंड होगा, अर्थात् :-

"(ए) चिकित्सा व्यय (Medical expenses) : 1 नवंबर, 2007 को और उसके पश्चात कोई अधिकारी स्वयं और अपने परिवार के लिए चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा, यदि ऐसे व्यय को स्वयं प्रमाणपत्र द्वारा प्रमाणित करता है और नीचे तालिका में निर्धारित अनुसार दावा की गयी राशियों के लिए विवरण प्रस्तुत करता है, यथा:

**"तालिका"**

ग्रेड (1)	प्रतिपूर्ति की उच्चतम सीमा (2)
कनिष्ठ प्रबंधन और मध्यम प्रबंधन ग्रेड	रु.5100 या व्यय की गई राशि, जो भी कम हो
वरिष्ठ प्रबंधन और उच्च कार्यपालक ग्रेड	रु.6320 या व्यय की गई राशि, जो भी कम हो

**नोट -** (i) किसी अधिकारी को न ली गयी चिकित्सा राशि को संचित (accumulate) करने की अनुमति होगी और इस प्रकार संचित राशि कभी भी ऊपर तालिका में दी गयी राशि के तीन गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए, या

(ii) वर्ष 2007 के लिए चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति दो महीनों, अर्थात् नवंबर 2007 और दिसंबर 2007 के लिए समानुपातिक रूप से बढ़ाई जाएगी।

व्याख्या - इस विनियम के उद्देश्य हेतु -

- (i) ऐसे मामलों में जहां अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो, वहां स्टाफ सदस्य के मामले में हॉस्पिटलाइजेशन प्रभार का 100% तथा स्टाफ के परिवारिक सदस्य के मामले में 75% तक प्रतिपूर्ति की जाएगी या;
- (ii) 1 मई, 2010 को और उस तारीख से इस विनियमन के अंतर्गत हॉस्पिटलाइजेशन व्यय की प्रतिपूर्ति कामगार कर्मचारी हेतु द्विपक्षीय समझौते दिनांक 27.04.2010 में निर्धारित हॉस्पिटलाइजेशन के नियमों व शर्तों के अनुसार होगी। यह निम्न तालिका में निर्धारित की गई सीमाओं के अध्यक्षीन होगी।

**"तालिका"**

(ए) कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल I और मध्यम प्रबंधन ग्रेड स्केल II एवं III	(i) <u>विस्तर प्रभार</u> स्वयं - रु.700 प्रति दिन परिवारिक सदस्य - रु.525 प्रति दिन (ii) <u>अन्य प्रभार</u> कामगार कर्मचारियों पर लागू हॉस्पिटलाइजेशन योजना के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं के 125% की दर पर
(बी) वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल IV एवं V और उच्च कार्यपालक ग्रेड स्केल VI एवं VII	(i) <u>विस्तर प्रभार</u> स्वयं - रु.900 प्रति दिन परिवारिक सदस्य - रु.675 प्रति दिन (ii) <u>अन्य प्रभार</u> कामगार कर्मचारियों पर लागू हॉस्पिटलाइजेशन योजना के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं के 150% की दर पर

9. कथित विनियमों के विनियम 25 में, उप- विनियम (2) के बदले, निम्नलिखित उप-विनियम होगा, अर्थात् :

"(2) उप विनियम (1) में किसी बात के होते हुए, बैंक को इस बात का अधिकार होगा कि वह अधिकारी को रिहायिशी आवास उपलब्ध कराये, जिसके लिए अधिकारी, 1 नवंबर, 2007 को और उक्त तारीख से, वह जिस वेतनमान में है उसके पहले चरण मूल वेतन के 1.20% के बराबर राशि या मानक किराया, इनमें से जो भी कम हो, का भुगतान करेगा :

यदि ऐसे आवासों में जहां अधिकारी को फर्नीचर उपलब्ध कराया गया है, तो बैंक द्वारा उस अधिकारी से, वह जिस वेतनमान में है उसके पहले चरण में मूल वेतन के 0.25% के बराबर की राशि वसूली जाए।

और जहां बैंक द्वारा ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई गई है वहां बिजली, पानी, गैस और रखरखाव प्रभार का वहन अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

10. कथित विनियमों के विनियम 36 में, उप-विनियम(2) के पश्चात, निम्न उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

"(3) 1 मई, 2010 से, 12 महीनों की कुल अवधि के अंतर्गत गर्भाशयोच्छेदन (hysterectomy) के मामले में अधिकतम 45 दिनों की छुट्टी भी प्रदान की जा सकती है।"

11. कथित विनियमों के विनियम 41 में, उप विनियम (4) में, खंड (ए) के बदले निम्नलिखित वाक्यांश होगा, अर्थात् :

'(a) विराम भत्ता - 1 मई, 2010 से, नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में दिये गये ग्रेड या स्केल में आने वाला अधिकारी इसके साथ कॉलम (2) में निर्धारित किये गये तदनुसूची दरों पर प्रति दिन के हिसाब से विराम भत्ता पाने का पात्र होगा। यथा :



**" तालिका "**

अधिकारी का ग्रेड/स्केल	बड़ी 'ए' वर्ग के शहर	क्षेत्र I	अन्य स्थान
(1)	(2)		
	रु.	रु.	रु.
स्केल IV और ऊपर के अधिकारी	1000	800	700
स्केल I/II/III के अधिकारी	800	700	600

बशर्ते यह कि स्केल IV और ऊपर वाले अधिकारियों के मामले में चार मेट्रो शहरों यथा- दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नै में कार्यालय से बाहर किसी काम के लिए विराम भत्ता रु.1200 प्रति दिन के हिसाब से देय होगा और स्केल I या II या III के लिए प्रति दिन विराम भत्ता रु.1000 होगा।

यदि बतायी गई अनुपस्थिति 8 घंटों से कम किंतु चार घंटे से अधिक हो तो, उपर्युक्त दरों की आधी दरों पर विराम भत्ता देय होगा।

व्याख्या : विराम भत्ते की गणना करने हेतु 24 घंटे की प्रत्येक अवधि या उसके बाद के किसी हिस्से को "प्रति दिन" माना जाएगा, जिसकी गणना हवाई यात्रा के मामले में प्रस्थान हेतु रिपोर्टिंग टाइम और अन्य मामलों में प्रस्थान के लिए निर्धारित समय से लेकर पहुंचने के वास्तविक समय तक की जाएगी और जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि 24 घंटे से कम है वहां "प्रति दिन" का अर्थ उस अवधि से होगा जो आठ घंटों से कम की न हो।

12. कथित विनियमों के विनियम 42 में, उप-विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

"(4) 1 मई, 2010 को और उक्त तारीख से, वह अधिकारी जो स्थानान्तरित हो, नीचे दी गई तालिका के अनुरूप पैकेजिंग, स्थानीय आवागमन, समान का बीमा करने आदि से संबंधित खर्चों के लिए एकमुश्त राशि आहरित करने का पात्र होगा :

**"तालिका"**

ग्रेड	एकमुश्त राशि
उच्च कार्यपालक और वरिष्ठ प्रबंधन	रु.12,000
मध्यम प्रबंधन और कनिष्ठ प्रबंधन	रु.9,000

13. कथित विनियमों के विनियम 44 में, उप-विनियम (3) में, निम्नलिखित प्रावधान शामिल जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

" बशर्ते कि 1 मई 2010 से, कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड वेतनमान I का अधिकारी अवकाश यात्रा रियायत का लाभ लेते समय न्यूनतर किराये वाली इकोनॉमिक क्लास में हवाई यात्रा करने का पात्र होगा। ऐसे मामले में वास्तविक किराए या की गयी यात्रा की दूरी हेतु, एंसी-प्रथम श्रेणी के लिए लागू किराए, इनमें से जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जाएगी और यही नियम 1000 किमी से कम दूरी के लिए अवकाश यात्रा रियायत का लाभ लेते समय मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल II और III के अधिकारी पर भी लागू होंगे।

14. कथित विनियमों के विनियम 45 में -

(i) उप-विनियम (1) में, निम्नलिखित प्रावधान जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

" बशर्ते यह कि 1 अप्रैल, 2010 को और उक्त तारीख से बैंक की सेवा में नियुक्त होने वाले अधिकारियों के लिए कोई भी भविष्य निधि उपलब्ध नहीं होगी।"

(ii) उप-विनियम (3) में, खंड (बी) के बाद और नोट से पूर्व, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

“(सी) जो अधिकारी अंशदायी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत शामिल है, और जिन्होंने पेंशन योजना के विकल्प का चयन नहीं किया है, वे अंशदायी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत जारी रह सकते हैं।”;

(iii) उप-विनियम (3), के बाद निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा :-

“1 अप्रैल 2010 को अथवा उसके बाद बैंक में सेवारंभ करने वाले अधिकारियों की परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) के तहत शामिल किया जाएगा, जहाँ भारत सरकार की अधिसूचना सं.एफ.नं.5/7/2003 – ईसीबी एण्ड पीआर दिनांक 22 दिसंबर, 2003, समय-समय पर यथा संशोधित, के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित नई पेंशन योजना के अनुरूप अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधानों के अनुसरण में संबंधित अधिकारी मंहगाई भत्ता सहित अपने वेतन के 10% का अंशदान करेगा और बैंक भी उसके समान राशि का अंशदान करेगा।”

15. कथित विनियमों की अनुसूची के बदले, निम्नलिखित अनुसूची होगी:-

“देना बैंक (अधिकारियों) सेवा विनियम 1979 की अनुसूची”

[विनियम 23 के उप-विनियम (2) देखें]

1 नवंबर, 2017 से प्रभावी कोई अधिकारी विशेष क्षेत्र भत्ते के लिए तब तक पात्र होगा जब तक उसमें पूर्ण या आंशिक आशोधन नहीं किया जाता, जैसा कि नीचे दी गयी तालिका में निर्दिष्ट है:-

तालिका

क्र.सं.	क्षेत्र	भत्ता (रु.)	
		रु.14,700/- से कम वेतन	रु.14,700/- से अधिक वेतन
1	2	3	4
1.	<b>मिज़ोरम</b> (ए) मिज़ोरम का चिमतुईपुई जिला और ऐसे क्षेत्र जो मिज़ोरम के लुंगलेई जिले में लुंगलेई कस्बे से 25 किमी से अधिक दूरी पर हों (बी) मिज़ोरम के लुंगलेई कस्बे से 25 किमी से ज्यादा दूर स्थित क्षेत्रों को छोड़कर पूरा लुंगलेई जिला (सी) मिज़ोरम का पूरा ऐजावल जिला	2000 1600 1200	2600 2100 1500
2.	नागालैण्ड	1600	2100
3.	अंडमान और निकोबार द्वीप (ए) उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान, छोटा अंडमान, निकोबार और नारकोनड द्वीप (बी) दक्षिण अंडमान (पोर्ट ब्लेयर को मिलाकर)	2000 1600	2600 2100
4.	सिक्किम	2000	2600
5.	लक्षद्वीप द्वीप	2000	2600
6.	आसाम	320	400
7.	मेघालय	320	400
8.	त्रिपुरा (ए) त्रिपुरा के कठिन क्षेत्र (बी) कठिन क्षेत्रों को छोड़कर पूरा त्रिपुरा	1600 1200	2100 1500
9.	मणिपुर	1200	1500

10.	अरुणाचल प्रदेश (ए) अरुणाचल प्रदेश का कठिन क्षेत्र (बी) अन्य जटिल क्षेत्रों को छोड़कर पूरा अरुणाचल प्रदेश	2000 1600	2600 2100
11.	जम्मू और कश्मीर (ए) कठुआ जिला : नियाबत बानी, लोही, मल्हार और माछोडी	2000	2600
	(बी) उधमपुर जिला : (i) डूडू बसंतगढ़, लंदर भमग इलाका, भाग 2(बी) में शामिल क्षेत्र छोड़कर (ii) मोहरे तहसील में लम्बन क्षेत्र से गोयल क्षेत्र तक और कैसी क्षेत्र से अरनास क्षेत्र तक	2000 1600	2600 2100
	(सी) डोडा जिला : किश्तवार तहसील में पद्मे और निबत नौगम के इलाके (डी) लेह जिला : जिले में सभी स्थान (ई) बारामूला जिला: (i) पूरा गुरेज – निराबत, तंगदार सब-डिवीजन और केरन इलाका (ii) मचिल (एफ) पूंछ और राजौरी जिला : पूंछ और राजौरी शहर छोड़कर पूंछ और राजौरी के क्षेत्र तथा सुंदरबनी और दोनों जिलों के अन्य शहर (जी) उपरोक्त (ए) से (एफ) में जो क्षेत्र शामिल नहीं हैं, लेकिन जो वास्तव में नियंत्रण रेखा से 8 किमी के अंतर्गत हैं अथवा ऐसे स्थल जो राज्य सरकार द्वारा अपने स्टाफ के लिए समय-समय पर बोर्डर भत्ते के लिए अर्हक क्षेत्र घोषित किए गए हों।	2000 2000 2000 1600 1200 1200	2600 2600 2600 2100 1500 1500
12.	<b>हिमाचल प्रदेश</b> (ए) चम्बा जिला (i) पांगी तहसील, भरमोर तहसील, पंचायत : बडगांव, बजौल, देओल कुगटी, नयागाम और टुंडाह, ग्राम : जगत ग्राम पंचायत का घाटू, चहाता ग्राम पंचायत का कनारसी (ii) भरमोर तहसील उपरोक्त (i) मद में दिये गये पंचायत और गांवों को छोड़कर। (iii) भतियात तहसील में झंडू पंचायत, चुराह तहसील, डलहौजी शहर (बानीखेत प्रौपर को मिलाकर)	2000 1600 1200	2600 2100 1500

<p>(बी) किन्नौर जिला</p> <p>(i) असरंग, चितकुल और हांगो कुनो/चारंग पंचायत, 15/20 क्षेत्र में छोटा खंबा, नाथपा और रूपी ग्राम पंचायत, पूह उप-खंड, ऊपर निर्दिष्ट पंचायत क्षेत्रों को छोड़कर</p> <p>(ii) उपरोक्त (ए) में शामिल क्षेत्रों के अलावा पूरा जिला</p> <p>(सी) कुल्लू जिला :</p> <p>(i) निरमांड तहसील का 15/20 क्षेत्र जिसमें खारगा, कुश्वर और सारगा ग्राम पंचायत शामिल हैं।</p> <p>(ii) आउटर-सराज (निर्मांड तहसील में जकात-खाना और बुरो गाँव छोड़कर) और सम्पूर्ण जिला, आउटर-सराज और पंद्रहवीस का परगना छोड़कर, लेकिन तहसील निमांड के बुरो और जगत-खाना गावों को मिलाकर</p> <p>(डी) लाहौल और स्पीति जिला :</p> <p>लाहौल और स्पीति का पूरा क्षेत्र</p> <p>(ई) शिमला जिला :</p> <p>(i) रामपुर तहसील का 15/20 क्षेत्र जिसमें कूट, लावना सदाना, सरपारा और चडी – बरांडा पंचायत शामिल हैं</p>		<p>2000</p> <p>1600</p> <p>2000</p> <p>1200</p> <p>2000</p> <p>2000</p>	<p>2600</p> <p>2100</p> <p>2600</p> <p>1500</p> <p>2600</p> <p>2600</p>
	<p>(ii) दोरा-कवर तहसील, रामपुर में दरकली ग्राम पंचायत, कशपथ तहसील और मुनीश, परगना सराहन की घोरी चैबिस।</p> <p>(iii) चोपाल तहसील और घोरिस, पंजगांव, पटसनौ, नौबिस और परगना सराहन की तीन कोठी, तकलेष क्षेत्र की देओथी ग्राम पंचायत, परगना बराबिस रामपुर तहसील का रामपुर कस्बा और परगना रामपुर का घोरी नोग, शिमला कस्बा और उसका नगर परिसर (धाली, जतोग, कसुम्पति, मशोब्रा, तारादेवी और टूटू)</p>	<p>1600</p> <p>1200</p>	<p>2100</p> <p>1500</p>
<p>(एफ) कांगड़ा जिला :</p> <p>(i) बड़ा भंगाल और छोटा भंगाल के क्षेत्र</p>		<p>1600</p>	<p>2100</p>
	<p>(ii) कांगड़ा जिले का धर्मशाला कस्बा और नगर पालिका सीमा से बाहर स्थित निम्नलिखित कस्बे लेकिन धर्मशाला कस्बे में शामिल – विमेन्स आईटीआई, दारी, मिक्नेनिकल वर्कशॉप, रामनगर, शिशु कल्याण और शहर एवं देश आयोजना कार्यालय, सकोह, लोअर सकोह में सीआरएसएफ कार्यालय, कांगड़ा दूध आपूर्ति योजना, दूगैर, एचआरटीसी वर्कशॉप, सधेर, आंचलिक (जोनल) मलेरया कार्यालय, दारी वन निगम कार्यालय, शामनगर, चाय फैक्ट्री, दारी, आई.पी.एच. उप-खण्ड, दान, निपटान (सेटलमेंट) कार्यालय, शामनगर, हिनवा प्रोजेक्ट, शामनगर।</p> <p>पालमपुर के एचपीकेवीवी कैम्पस को मिलाकर कांगड़ा जिले का पालमपुर शहर और नगर पालिका सीमा से बाहर स्थित निम्नलिखित कार्यालय लेकिन पालमपुर शहर में शामिल –</p>	<p>1200</p>	<p>1500</p>

	एच.पी.कृषि विश्व-विद्यालय कैम्पस, मवेशी विकसित कार्यालय/इंडो-जर्मन कृषि वर्कशाप/एचपीपीडब्ल्यूडी प्रभाग, बुंदला, इलेक्ट्रिकल उप-खंज, लोहना, डी.पी.ओ. निगम, बुंदला, इलेक्ट्रिकल एचईएसईई खंड, घुग्गर।		
	(जी) मण्डी जिला : जोगिन्दरनगर तहसील की छहार वैली, बग्रा, चत्री, छोटधर, गरागुशैम, गाटू, गरयास, जन्मेहली, जरयार, जोहर, कल्हानी, कल्वां, खोलनल, लोथ, सिलिवागी, सोमाचन, थच्छर, टाची, थाना की पंचायते सुनाग तहसील में, धर्मपुर ब्लॉक – बिंगा, कमलाह, सकलाना, टनयार और लाराखोलाह की पंचायतें, करसोग तहसील – बालीधर, बग्रा, गोपालपुर, खजोल, महोग, मेहुडी, मांज, पेखी, सैज, सराहन और तेबन की पंचायतें, सुंदरनगर तहसील – बोही, बटवारा, धान्यारा, पौराकोठी, सेरी और शौजा।	1200	1500
	(एच) सिरमौर जिला : बानी, बखाली (पठड तहसील), भारोग भेनेरी (पैनता तहसील), बिरला (नहान तहसील), दिब्बेर (पछड तहसील) और थाना कलौगा (नाहन तहसील) और थानसगीरी भूभाग की पंचायतें।	1200	1500
	(आई) सोलन जिला : मंगल पंचायत	320	400
	(जे) उपरोक्त (ए) से (आई) तक की मदों में शामिल नहीं किए गए हिमाचल प्रदेश के शेष क्षेत्र		
13.	<b>उत्तराखण्ड</b> चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चम्पावत जिलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।	2000	2600

**व्याख्यात्मक ज्ञापन**

जिन विनियमों को पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी किया गया था वे इस संबंध में संबंधित बैंकों द्वारा दिए गए निर्दिष्ट अध्यादेश के आधार पर सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ एवं शीर्ष स्तर पर बैंकों के अधिकारी संघों के बीच हस्ताक्षरित संयुक्त नोट के सहमत निबंधन एवं शर्तों के अनुसार है।

बी. एम. नन्दा, महाप्रबंधक (मानव संसाधन)

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/36/18]

**नोट:** मुख्य विनियम भारत के गजट में दिनांक ----- को प्रकाशित हुआ था और उसके पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित हुई, यथा :—

क्रम संख्या

अधिसूचना संख्या

दिनांक

1

2

3

**DENA BANK  
NOTIFICATION**

Mumbai, the 6th March, 2018

**F.No.HO/HRM/IR/NOTE-79/2018.**—In exercise of the powers conferred by section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the DENA BANK in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the DENA BANK (Officers') Service Regulations, 1979, namely:-

1. (1) These regulations may be called the DENA BANK Officers') Service (Amendment) Regulations, 2017.
- (2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of November, 2007, except as otherwise provided in these regulations.
2. In the DENA BANK (Officers') Service Regulations, 1979 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3,-

- (i) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:-

‘(f) “family” means the spouse of the officer, wholly dependent unmarried children (including step children and legally adopted children), physically challenged brother or sister with forty per cent, or more disability and parents ordinarily residing with and wholly dependent on the officer’.

**Explanation.-** For the purposes of this clause a child or parent or physically challenged brother or sister shall be deemed to be dependent on the officer if the monthly income of such child, parent, brother or sister does not exceed Rs.3,500 per month :

Provided that if the income of one of the parents exceeds Rs.3,500 per month or the aggregate income of both the parents exceeds Rs.3,500 per month, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer.’

- (ii) Clause (o) shall be omitted.

3. In regulation 4 of the said regulations,-

- (i) sub-regulation (4A) shall be omitted;
- (ii) after sub-regulation (4A) as so omitted, the following sub-regulations shall be inserted, namely:-

“(5) With effect from the 1<sup>st</sup> November, 2007, the scales of pay specified against each grade shall be as under :

- (a) Top Executive Grade

Scale VII = Rs.46800 – 1300/4 – 52000

Scale VI = Rs.42000 - 1200/4 – 46800

- (b) Senior Management Grade

Scale V = Rs.36200 – 1000/2 – 38200 – 1100/2 - 40400

Scale IV = Rs.30600 – 900/4 – 34200– 1000/2 – 36200

- (c) Middle Management Grade

Scale III = Rs.25700 - 800/5— 29700 - 900/2 - 31500

Scale II = Rs.19400 - 700/1 - 20100 -800/10 - 28100

- (d) Junior Management Grade

Scale I = Rs.14500-600/7- 18700-700/2- 20100- 800/7-25700.

**Explanation.-**Every officer who is governed by the scales of pay in force as on the 31<sup>st</sup> October, 2007 shall be fitted in the scale of pay set out in this sub-regulation as on 1<sup>st</sup> November, 2007 on stage to stage basis, i.e. on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual except where provided otherwise.

- (6) Nothing in sub-regulations (1), (2), (3), (4) and (5) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades.”.

4. In regulation 5 of the said regulations, -

- (a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation, shall be substituted, namely: -

“(1) Subject to the provisions of sub-regulation (5) of regulation 4, on and from the 1<sup>st</sup> November, 2007, the increments shall be granted subject to the following, namely: -

- (a) the increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation (5) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;
- (b) officers in Junior Management Grade Scale I who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale II after reaching maximum of the higher scale shall be eligible for four stagnation increments for every three completed years of service of which first two shall be Rs.800 each and next two Rs.900 each:

Provided that officers who have completed three years or more after receipt of the second stagnation increment as on 1st November, 2007 shall get the third stagnation increment on 1st November, 2007 and another stagnation increment on or after the 1<sup>st</sup> November, 2008 on their completion of six years after receipt of second stagnation increment;

- (c) officers in Middle Management Grade Scale II who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale III after reaching maximum of higher scale shall be eligible for three stagnation increments of Rs.900 each for every three completed years of service:

Provided that officers who have completed three years or more after receipt of the first stagnation increment as on the 1st November, 2007 shall get the next stagnation increment with effect from the 1st November, 2007 and a subsequent stagnation increment on or after the 1st November, 2008 on their completion of six years after receipt of the first stagnation increment:

Provided further the officers appointed to or promoted in substantive Middle Management Grade Scale III, shall be eligible for four stagnation increments of Rs.900 each for every three completed years of service or :

Provided also that the officers who have already received two stagnation increments and completed more than three years of service after receipt of second stagnation increment as on the 1st November, 2007 shall get the third stagnation increment on the 1st November, 2007 and the fourth stagnation increment, on or after the 1<sup>st</sup> November, 2008 on completion of six years after receipt of second stagnation increment.

**Explanation.-** Grant of such increments in the next higher scale under this sub-regulation shall not amount to promotion and the privileges, perquisites, duties and responsibilities of the officers shall continue as of their substantive posts.

- (b) in sub-regulation (2),-

- (i) in the Explanation, after clause (e) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

“(f) on and from the 1st day of November, 2007, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as under:-

TABLE

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.410 per month one year after reaching maximum of the Scale.
Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.410 per month after one year on reaching maximum of the Scale. (ii) Rs.1030 per month after two years on reaching maximum of the Scale;

Provided that an Officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification the first installment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent installments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first installment of Professional Qualification Pay:

Provided further that in a case where an officer, has already acquired any of the above qualifications and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification, he may be granted the Professional Qualification Pay, with effect from the 1<sup>st</sup> November 2007 or the date of acquiring such qualification/s, whichever is later.”;

(ii) in the Note, for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:-

“(v) if an officer, as on the 27<sup>th</sup> April 2010 has already acquired any of the said qualifications referred to in clause (iv) and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification, he shall be granted the Professional Qualification Pay, with effect from the 1<sup>st</sup> day of November, 2007 or the date of acquiring such qualification, whichever is later.”;

(c) in sub-regulation (3),-

(i) after clause (d) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

“(e) on and from the 1st November, 2007, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance shall be at the following rates and shall remain frozen for the entire period of service:-

TABLE

Increment Component (Rs.)	Dearness Allowance as on 01.11.2007 on the increment components (Rs.)	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (Rs.)
(A)	(B)	(C)
800	58	858
900	65	965
1000	72	1072
1100	79	1179
1200	86	1286
1300	94	1394”,

(ii) in the Note, for clauses (i) and (ii), the following clauses shall be substituted, namely:-

“(i) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as indicated under column (C) of the Table under clauses (b), (c), (d) or (e) shall be payable to those officers who are provided with bank's accommodation.

(ii) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be the aggregate amount specified under columns (A) and (B) of the Table under clause (e) and House Rent Allowance drawn by the concerned officer employees when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulations (2), (3), (4) or (5) of regulation 4 is earned.”;

(iii) clause (e) occurring after the Note shall be renumbered as sub-clause (v) thereof and for clause (v) as so numbered, the following clause be substituted, namely:-

“(v) An officer who has earned the advance increment as in clause (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c), (d) or (e) above, one year after reaching the maximum of the scale”;



5. In regulation 21 of the said regulations, -

- (i) in sub-regulation (3), the Note shall be omitted;
- (ii) in sub-regulation (4), the Note shall be omitted;
- (iii) after sub-regulation (4), the following sub-regulation and Note shall be inserted, namely:-

“(5) On and from the 1<sup>st</sup> day of November, 2007, dearness allowance shall be payable for every rise or fall of four points over 2836 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100 at 0.15% of Pay.

Explanation.- For the purposes of this sub-regulation,-

- (a) “pay” for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments;
- (b) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in Explanations (c), (d), (e) and (f) to sub-regulation (2) of regulation 5 shall rank for dearness allowance’.

6. In regulation 22 of the said regulations, for sub-regulations(1) and (2), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-

“(1)on and from the 1<sup>st</sup> day of November, 2002,

- (a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.75 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;
- (b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely:

**TABLE**

Where the place of work is in	HRA payable shall be
(1)	(2)
(i) Major “A” Class Cities and Project Area Centres in Group A	8.5% of Pay
(ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group B	7.5% of Pay
(iii) Other places	6.5% of Pay;

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 1.75 per cent of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent of the House Rent Allowance payable as per column (2) of the above Table.

(2)on and from the 1<sup>st</sup> day of November, 2007, -

- (a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.20 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;
- (b)where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely: -

**TABLE**

Where the place of work is in	HRA payable shall be
(1)	(2)
(i) Major “A” Class Cities and Project Area Centres in Group A	8.5% of Pay
(ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group B	7.5% of Pay
(iii) Other places	6.5% of Pay

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him

shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 1.20 per cent of Pay in the first stage of the Scale of Pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent of the House Rent Allowance payable as per aforesaid rates mentioned in column (2) above.

Note.- The claims of officers for House Rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall also be restricted to 150 per cent of House Rent Allowance as hitherto.”;

7. In regulation 23 of the said regulations,-

- (i) in sub-regulation (1), for the figures, letters and words “1<sup>st</sup> day of November 2002”, the figures, letters and words “1<sup>st</sup> day of November 2007” shall be substituted;
- (ii) in sub-regulation (2), for the figures, letters and words “1<sup>st</sup> day of November 2002, the figures, letters and words “1<sup>st</sup> day of November 2007” shall be substituted;
- (iii) for sub-regulations (3), (4) and (5), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-

“(3) On and from the 1<sup>st</sup> day of November, 2007, if an officer is serving in an area to be specified as Project Area falling in Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs.290 per month or Rs.255 per month according to the classification of area as Group A or Group B.

(4) On and from the 1<sup>st</sup> day of November, 2007, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs.700 per month from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year in respect of all the children, provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.

(5) On and from the 1<sup>st</sup> day of May, 2010, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75 per cent of pay subject to a maximum Rs.2300 per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the Bank’s service at that place:

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 4 per cent of his pay subject to a maximum Rs.1200 per month:

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the Bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at the rate of 4 per cent of his pay subject to a maximum Rs.1200 per month.”;

- (iv) for sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(8) on and from the 1<sup>st</sup> day of November 2007, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs.165 per month.”;

- (v) in sub-regulation (10),-

(a) for the figures, letters and words “1<sup>st</sup> day of November 2002”, the figures, letters and words “1<sup>st</sup> day of November, 2007” shall be substituted;

(b) for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

“TABLE

Place (1)	Rate (2)
(i) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2% of pay subject to a maximum of Rs.550 per month
(ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2½% of pay subject to a maximum of Rs.680 per month

(iii) Place with an altitude of 3000 metres and above	5% of pay subject to a maximum of Rs.1570 per month”;
---	---

8. In regulation 24 of the said regulations, in sub-regulation (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

“(a) Medical Expenses.- On and from the 1<sup>st</sup> day of November 2007, an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer’s own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the table below, namely:-

**TABLE**

Grade	Maximum limit of reimbursement
Junior Management and Middle Management Grade	Rs.5100 or the amount incurred whichever is less
Senior Management and Top Executive Grade	Rs.6320 or the amount incurred whichever is less

Note.- (i) an officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above or;

(ii) for the year 2007, the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, that is, November 2007 and December, 2007.

Explanation. - for the purposes of this regulation,-

- (i) hospitalisation charges shall be reimbursed to the extent of 100 per cent in the case of an officer and 75 per cent, in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalization or;
- (ii) on and from the 1<sup>st</sup> day of May, 2010, reimbursement of hospitalisation expenses under this regulation shall be in accordance with the terms and conditions of Hospitalisation Scheme as laid down under the Bipartite Settlement dated the 27<sup>th</sup> day of April, 2010 for workmen employees, subject to the limits as specified in the table below, namely:-

**TABLE**

(a) Junior Management Grade Scale I and Middle Management Grade Scales II and III.	(i) Bed Charges Self – Rs.700 per day Family – Rs.525 per day (ii) Other charges At the scale of 125% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.
(b) Senior Management Grade Scales IV and V and Top Executive Grade Scales VI and VII.	(i) Bed Charges Self – Rs.900 per day Family – Rs.675 per day (ii) Other charges At the scale of 150% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.”;

9. In regulation 25 of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation(1), it shall be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1st day of November, 2007, a sum equal to 1.20 per cent, of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.25 per cent of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed shall be recovered by the Bank from him:

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.”.

10. In regulation 36 of the said regulations, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely :-

“(3) With effect from the 1<sup>st</sup> day of May 2010, within the overall period of 12 months, leave may also be granted in case of hysterectomy upto a maximum of 45 days.”.

11. In regulation 41 of the said regulations, in sub-regulation (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

‘(a) Halting Allowance – On and from the 1st day of May, 2010, an officer in the Grades or Scales set out in column (1) of the Table below shall be entitled to ‘per diem’ Halting Allowance at the corresponding rates set out in column (2) thereof, namely:-

TABLE

Grades/Scales of officers	Major ‘A’ Class cities	Area I	Other Places
(1)	(2)		
	Rs.	Rs.	Rs.
Officers in Scale IV and above	1000	800	700
Officers in Scale I/II/III	800	700	600

Provided that in the case of officers in Scale IV and above, Halting Allowance payable per diem while on outstation work at the four metros, viz., Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai, shall be Rs.1200 and for officers in Scale I or II or III, the per diem Halting Allowance shall be Rs.1000:

Provided further that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation.- For the purpose of computing Halting allowance “per diem” shall mean each period of twenty-four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty-four hours, “per diem” shall mean a period of not less than eight hours.’.

12. In regulation 42 of the said regulations, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(4) On and from the first day of May 2010, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc., as specified in the Table below, namely:-

“TABLE

Grade	Lump Sum
Top Executive and Senior Management	Rs.12,000
Middle Management and Junior Management	Rs.9,000”.

13. In regulation 44 of the said regulations, in sub-regulation (3), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that with effect from the 1<sup>st</sup> May 2010, an officer in Junior Management Grade Scale I while availing Leave Travel Concession shall be entitled to travel by air in the lowest fare economy class in which case the reimbursement will be the actual fare or the fare applicable to AC First Class

fare by train for the distance traveled, whichever is less and the same rules shall apply to an officer in Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III while availing Leave Travel Concession where the distance is less than 1000 kms.”.

14. In regulation 45 of the said regulations, -

(i) in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that there shall be no Provident Fund to Officers joining the services of the Banks on or after the 1st day of April, 2010.”;

(ii) in sub-regulation (3), after clause (b) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

“(c) Officers who are covered under the Contributory Provident Fund Scheme who do not opt for Pension Scheme shall continue under the Contributory Provident Fund Scheme.”;

(iii) after sub-regulation(3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(4) The officers joining the services of the Bank on or after the 1st day of April 2010 shall be covered by a Defined Contributory Pension Scheme, where the officer shall contribute ten per cent, of pay plus Dearness Allowance and the Bank shall make the similar amount of contribution in accordance with the provisions of the Contributory Pension Scheme in accordance with New Pension Scheme notified by the Central Government vide notification of the Government of India, F.No.5/7/2003-ECB & PR dated the 22<sup>nd</sup> December, 2003, as amended from time to time.”

15. For the Schedule to the said regulations, the following Schedule shall be substituted, namely:-

“Schedule to ..... DENA BANK ..... (Officers’) Service Regulations, 1979

(See sub-regulation (2) of regulation 23)

With effect from the 1st day of November, 2007, an officer shall be eligible for the Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the Table below, namely:-

**TABLE**

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs.14,700/-	Pay above Rs.14,700/-
1	2	3	4
1.	<b>Mizoram</b>		
	(a) Chimpuipui District of Mizoram and areas beyond 25 kms. from Lunglei Town in Lunglei District of Mizoram.	2000	2600
	(b) Throughout Lunglei District excluding areas beyond 25 kms. from Lunglei town of Mizoram.	1600	2100
	(c) Throughout Aizawl District of Mizoram	1200	1500
2.	<b>Nagaland</b>	1600	2100
3.	<b>Andaman and Nicobar Islands</b>		
	(a) North Andaman, Middle Andamans, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands	2000	2600
	(b) South Andaman (including Port Blair)	1600	2100
4.	<b>Sikkim</b>	2000	2600
5.	<b>Lakshadweep Islands</b>	2000	2600
6.	<b>Assam</b>	320	400

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs.14,700/-	Pay above Rs.14,700/-
1	2	3	4
7.	<b>Meghalaya</b>	320	400
8.	<b>Tripura</b> (a) Difficult areas of Tripura (b) Throughout Tripura except difficult areas.	1600 1200	2100 1500
9.	<b>Manipur</b>	1200	1500
10.	<b>Arunachal Pradesh</b> (a) <b>Difficult areas of Arunachal Pradesh</b> (b) Throughout Arunachal Pradesh other than difficult areas.	2000 1600	2600 2100
11.	<b>Jammu and Kashmir</b> (a) Kathua District: Niabat Bani, Lohi, Malhar and Machhodi	2000	2600
	(b) Udhampur District: (i) Dudu Basantgarh, Lander Bhamag Illaqa, other than those included in Part 2(b). (ii) Areas upto Goel from Kamban Side and areas upto Arnas from Keasi side in Tehsil Mohre.	2000 1600	2600 2100
	(c) Doda District: Illaquas of Padder and Niabat Nowgam in Kishtwar Tehsil	2000	2600
	(d) Leh District : All places in the District	2000	2600
	(e) Barmulla District (i) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar Sub-Division and Keran Illaqua (ii) Matchill	2000 1600	2600 2100
	(f) Poonch and Rajouri District : Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two Districts.	1200	1500
	(g) Areas not included in items (a) to (f) above, but which are within the distance of 8 kms. from the line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for border allowance from time-to-time by the State Government for their own staff.	1200	1500
12.	<b>Himachal Pradesh</b> (a) Chamba District (i) Pangi Tehsil, Bharmour Tehsil, Panchayats : Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tundah, Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata (ii) Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and Villages included in item (i) above.	2000 1600	2600 2100
	(iii) Jhandru Panchayat in Bhatiyat Tehsil, Churah Tehsil, Dalhousie Town (including Banikhet proper).	1200	1500
	(b) Kinnaur District: (i) Asrang, Chitkul and Hango Kuno/ Charang Panchayats, 15/ 20 Area comprising the Gram Panchayats of Chhota Khamba, Nathpa and Rup, Pooh Sub-Division, excluding the Panchayat Areas specified above. (ii) Entire District other than Areas included in (a) above.	2000 1600	2600 2100
	(c) Kullu District: (i) 15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga (ii) Outer-Saraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire District excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burrow of Tehsil Nirmand).	2000 1200	2600 1500
	(d) Lahaul and Spiti District :		

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs.14,700/-	Pay above Rs.14,700/-
1	2	3	4
	Entire area of Lahaul and Spiti	2000	2600
	(e) Shimla District :		
	(i) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chadi-Brandana.	2000	2600
	(ii) Dora-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish, Ghori Chaibis of Pargana Sarahan.	1600	2100
	(iii) Chopal Tehsil and Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan, Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, Pargana Barabis, Kasba Rampur and Ghori Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil, Simla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu).	1200	1500
	(f) Kangra District:		
	(i) Areas of Bara Bhargal and Chhota Bhargal	1600	2100
	(ii) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town-Women's ITI, Dari, Mechanical Workshop, Ramnagar, Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, CRSF Office at lower Sakoh, Kangra Milk Supply Scheme, Dugiar, HRTC Workshop, Sadher, Zonal Malaria Office, Dari, Forest Corporation Office, Shamnagar, Tea Factory, Dari, I.P.H. Sub-Division, Dan, Settlement Office, Shamnagar, Hinwa Project, Shamnagar. Palampur Town of Kangra District including HPKVV Campus at Palampur and the following offices located outside its municipal limits but included in Palampur Town – H.P. Krishi Vishwavidhalaya Campus, Cattle Development Office/Jersey Farm, Banuri, Sericulture Office/Indo-German Agriculture Workshop/HPPWD Division, Bundla, Electrical Sub-Division, Lohna, D.P.O. Corporation, Bundla, Electrical HESEE Division, Ghuggar.	1200	1500
	(g) Mandi District:		
	Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in thunag Tehsil- of Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gatoo, Garyas, Janjehli, Jaryar, Johar, Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Panchayats of Dharampur Block- Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil – Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar Tehsil – Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri and Shoja.	1200	1500
	(h) Sirmaur District:		
	Panchayats of Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil), BharogBheneri (Paonta Tehsil), Birla (Nahan Tehsil), Dibber (Pachhad Tehsil) and Thana Kasoga (Nahan Tehsil) and Thansgiri Tract	1200	1500
	(i) Solan District :		
	Mangal Panchayat.	1200	1500
	(j) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in items (a) to (i) above.	320	400
13.	<b>Uttarakhand</b> Areas under Chamoli, Pithoragarh, Uttarkashi, Rudraprayag and Champavat Districts.	2000	2600”

**EXPLANATORY MEMORANDUM**

The Regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level officers' associations of the Banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

B.M. NANDA, General Manager (HRM)

[ADVT. -III/4/Exty./36/18]

**Note:** The principal regulations were published in the Gazette of India on \_\_\_\_\_ and subsequently amended vide following notifications, namely:-

1. No. \_\_\_\_\_, dated the \_\_\_\_\_, day of \_\_\_\_\_
- 2.
- 3.